बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 381805 पटना, दिनांक 31/07/18

ग्रा.वि.-7(विविध)-11/2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यान्वित करायी गयी योजनाओं के लंबित भुगतान के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 348294 दिनांक 15.01.2018, 352344 दिनांक 06.02.2018, 361258 दिनांक 20.03.2018, 363302 दिनांक 03.04.2018, 368051 दिनांक 03.04.2018, 372484 दिनांक 31.05.2018, 374560 दिनांक 13.06.2018, 375945 दिनांक 21.06.2018 एवं 376091 दिनांक 22.06.2018 ।

महाशय,

माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद सं0-5/लोक(पंचायत)10/13-8935/लोक में दिनांक 17.01.2018 को किये गये सुनवाई के क्रम में दिये गये निर्देश के आलोक में प्रासंगिक विभागीय पत्रांक 352344 दिनांक 06.02.2018 द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं के लंबित दायित्वों के भुगतान की कार्रवाई हेतु मजदूरी मद/ सामग्री मद के वित्तीय वर्ष 2015-16 से पूर्व के वर्षों में लंबित दायित्व के विस्तृत ब्यौरे की मांग की गई जिसके परिप्रेक्ष्य में अधिकांश जिलों से प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है ।

इस क्रम में माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 27.06.2018 को किये गये सुनवाई में पुन: आदेशित किया गया है कि वर्ष 2017-18 तक लंबित दायित्व के भुगतान के सघन समीक्षा की आवश्यकता है ताकि भारत सरकार से समन्वय कर लाभुकों को राशि का भुगतान किया जा सके ।

अतएव उक्त के आलोक में मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 तक लंबित दायित्वों के भुगतान से संबंधित वांछित सूचना संलग्न प्रपत्र में एक सप्ताह के अंदर विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन

31/7/18

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव